यू. पी.-पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024

सामान्य अध्ययन - VI

प्रश्न-पत्र - VI

खंड - अ

प्रश्न.1 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, इसके विकास में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों की भूमिका पर प्रकाश डालें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (UP), जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, एक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जिसका आधार मुख्यतः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं। यह राज्य स्थल-आवृत्त (landlocked) है, अतः भौतिक अवसंरचना (Infrastructure) और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग ने इसके आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँः

1. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था

- राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जिसमें 60% से अधिक जनसंख्या संलग्न है।
- प्रमुख फसलें: गेहूँ, धान, गन्ना, दालें।
- उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जिससे इसकी कृषि आधारित उद्योग प्रणाली को बल मिलता है।

2. औद्योगिक आधार

- विविध औद्योगिक क्षेत्रों की उपस्थिति: वस्त्र (जैसे वाराणसी), चमड़ा (कानपुर), हस्तशिल्प (मुरादाबाद), इलेक्ट्रॉनिक्स (नोएडा-ग्रेटर नोएडा)।
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के माध्यम से परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्रामीण रोजगार और निर्यात में वृद्धि।

3. सेवा क्षेत्र का विस्तार

- आईटी और ITES का तीव्र विकास (विशेषकर नोएडा और लखनऊ)।
- धार्मिक और विरासत पर्यटन (अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज) सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा।

अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढाँचे की भूमिकाः

1. परिवहन अवसंरचना

- **सड़क नेटवर्कः** भारत में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क; प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल, यमुना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
- **रेल मार्गः** सघन रेलवे नेटवर्क जो कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ता है।
- **हवाई अड्डे:** जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन; लखनऊ और वाराणसी के हवाई अड्डों का उन्नयन।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

2. ऊर्जा अवसंरचना

- थर्मल, हाइड्रो और सौर ऊर्जा स्रोतों से बिजली आपूर्ति में सुधार।
- सौर ऊर्जा पार्क और ग्रामीण विद्युतीकरण से औद्योगिक व कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा।

3. शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढाँचा

- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) जैसी परियोजनाओं का विकास।
- स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT योजना के तहत शहरी विकास और निवेश वातावरण में सुधार।

भौतिक संसाधनों की भूमिकाः

1. भूमि और जल संसाधन

- उपजाऊ गंगा के मैदान, जो उच्च कृषि उत्पादकता को संभव बनाते हैं।
- गंगा और यमुना जैसी नदियां – सिंचाई, मत्स्य पालन और परिवहन के लिए सहायक।
- भूजल स्रोतों की उपस्थिति, हालांकि जल-क्षय और प्रदूषण की चुनौतियां भी मौजूद हैं।

2. वन और खनिज संसाधन

- **तराई क्षेत्र के वन** – जैव विविधता और लघु वन आधारित उद्योगों को समर्थन।
- **सिलिका, चूना पत्थर, डोलोमाइट** जैसे खनिज – स्थानीय औद्योगिक उपयोग में सहायक।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे कृषि-प्रधान से हटकर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के संतुलित मिश्रण की ओर बढ़ रही है। इस विकास में बुनियादी ढांचा-विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा और शहरी सेवाएं, तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग प्रमुख कारक हैं। भविष्य में सतत संसाधन प्रबंधन और समान बुनियादी ढांचा विकास पर बल देना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर को कम किया जा सके और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.2 उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।

उत्तर– उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 राज्य सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन का एक अग्रणी केंद्र बनाना है। यह नीति भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है और इसका लक्ष्य उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन, निवेश आकर्षण, और रोजगार सृजन करना है।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की प्रमुख विशेषताएं:

1. उत्पादन लक्ष्य

- वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य।
- उर्वरक और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता जहाँ पहले से हाइड्रोजन की मांग है, ताकि ग्रे से ग्रीन हाइड्रोजन की ओर सुगम संक्रमण हो।

2. निवेश और रोजगार सृजन

- नीति के तहत 1.95 लाख करोड़ से अधिक का निवेश संभावित, 19 प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से।
- 2028 तक लगभग 1.20 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना, जिससे आर्थिक विकास और कौशल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

3. प्रोत्साहन और सब्सिडी

- **पूंजीगत अनुदान** (Capital Subsidy):
  - पहले पाँच परियोजनाओं को 40% तक की सब्सिडी (₹225 करोड़ तक की सीमा)।
  - अन्य परियोजनाओं को स्थान और स्केल के आधार पर 10%-30% की सब्सिडी।
- **कर में छूट:**
  - पहले 10 वर्षों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में 100% छूट।
- **भूमि एवं अवसंरचना सहायता:**
  - सरकार की भूमि 30 वर्षों के लीज पर रियायती दरों पर उपलब्ध।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता से भूमि आवंटन।

4. अवसंरचना विकास

- हाइड्रोजन हब्स, पाइपलाइनों, और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं का विकास।
- इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन के लिए ढाँचागत सहायता।
- कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी (CDR) इकाइयों को बढ़ावा, बायोगैस आदि के उत्सर्जन के पुन: उपयोग हेतु।

5. अनुसंधान और नवाचार

- **2 उत्कृष्टता केंद्र** (Centers of Excellence - CoEs) की स्थापना का प्रावधान:
  - स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण।
  - उन्नत टाइप-4 टैंक और फ्यूल सेल विकास।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन तकनीकों में नवाचार।
- सरकारी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा CoEs की स्थापना पर ₹50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता।

6. व्यवसाय सुविधा (Ease of Doing Business)

- सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से स्वीकृतियों में तेजी।
- भूमि बैंक, जल स्रोत, विद्युत उपलब्धता जैसे आंकड़ों की सार्वजनिक पहुँच।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को व्हाइट कैटेगरी में रखा गया है जिससे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया आसान होती है।

7. कौशल विकास

- ग्रीन हाइड्रोजन-रेडी वर्कफोर्स तैयार करने हेतु लक्षित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 एक समग्र और दूरदर्शी नीति है, जो राज्य को भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर करती है। यह नीति न केवल पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देती है, बल्कि अर्थव्यवस्था, निवेश, रोजगार और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी अनेक अवसर उत्पन्न करती है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.3 उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में इकोटूरिज्म के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर- ईको-पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदार यात्रा है, जो पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भलाई और शिक्षा को बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश, जो जैव विविधता में समृद्ध है, में ईको-पर्यटन पारिस्थितिक संतुलन और स्थानीय विकास के बीच संतुलन साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उत्तर प्रदेश में ईको-पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव

1. जैव विविधता का संरक्षण

- ईको-पर्यटन से संरक्षण के लिए जागरूकता और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई है।
- उदाहरण:
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (Project Tiger रिजर्व) में ईको-पर्यटन के चलते बाघ, दलदली बारहसिंगा और हिस्पिड हेयर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी और सुरक्षा बेहतर हुई है।

2. स्थानीय रोजगार और आजीविका

- स्थानीय समुदायों को गाइड, ईको-गार्ड और पर्यटन सुविधाओं में रोजगार मिला है।
- उदाहरण:
  - कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में प्रशिक्षित स्थानीय लोग ईको-गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे आजीविका के वैकल्पिक स्रोत बने हैं।

3. अवसंरचना विकास

- पर्यटन के लिए पर्यावरण-संवेदनशील ढाँचागत विकास हुआ है।
- उदाहरण:
  - चंद्रप्रभा अभयारण्य में ईको-हट्स, सौर प्रकाश व्यवस्था और पगडंडियाँ विकसित की गई हैं।

4. शिक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता

- पर्यावरणीय शिक्षा शिविरों, पक्षी दर्शन, और वन्यजीव फोटोग्राफी से जन-जागरूकता में वृद्धि हुई है।
- विशेष रूप से छात्रों और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत हुई है।

ईको-पर्यटन से संबंधित चुनौतियाँ और नकारात्मक प्रभाव

1. वहन क्षमता का अतिक्रमण

- पर्यटन सीजन में अधिक भीड़ से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- दुधवा जैसे क्षेत्रों में कचरा, आवासीय क्षेत्रों को नुकसान जैसे मुद्दे देखे गए हैं।

2. वन्यजीवों में व्यवधान

- अनियंत्रित वाहन आवाजाही, शोर और कैमरा फ्लैश से प्रजनन और व्यवहार में बाधा आती है।
- इससे जैव विविधता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

3. आर्थिक लाभों में असमानता

- कभी-कभी निजी टूर ऑपरेटर या बाहरी एजेंसियाँ अधिक लाभ ले जाती हैं।
- इससे स्थानीय समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाते।

4. अपर्याप्त निगरानी और नियमन

- सोहागी बड़वा और रानीपुर जैसे कम लोकप्रिय अभयारण्यों में नियमों का पालन नहीं होता।
- इससे पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ता है।

निष्कर्ष

- उत्तर प्रदेश में ईको-पर्यटन संरक्षण, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय विकास का एक प्रभावशाली माध्यम बन रहा है।
- इसकी सफलता के लिए आवश्यक है: स्थानीय भागीदारी, कड़ी निगरानी, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
- यदि रणनीतिक और समावेशी तरीके अपनाए जाएँ, तो ईको-पर्यटन सतत विकास का एक मॉडल बन सकता है।

प्रश्न.4 उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं?

उत्तर- भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) औद्योगिक और आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं रखता है।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी पहलों के माध्यम से राज्य निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है।

हालांकि, कई संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियाँ निवेश के इरादों को वास्तविक आर्थिक विकास में बदलने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्देः

1. आधारभूत संरचना की कमियाँ

- प्रमुख एक्सप्रेसवे (जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड) के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की कमी है।
- बिजली की अनियमित आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स की अक्षमताएँ संचालन लागत को बढ़ाती हैं।
- उदाहरणः पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में औद्योगिक गतिविधियों में पिछड़ा हुआ है।

2. भूमि अधिग्रहण और नियामक देरी

- भूमि स्वामित्व की जटिलता, बिखरी हुई जोतें और अधिग्रहण में देरी परियोजनाओं की समय-सीमा को प्रभावित करती हैं।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के बावजूद नौकरशाही की बाधाएँ बनी रहती हैं।
- **उदाहरणः** झांसी में डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण संबंधी देरी।

3. क्षेत्रीय विकास में असंतुलन

- निवेश मुख्यतः नोएडा, गाजियाबाद और NCR से सटे जिलों में केंद्रित है।
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता मिलती है।
- उदाहरणः 2023 इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित MoUs में से 50% से अधिक पश्चिमी यूपी पर केंद्रित थे।

4. कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताएँ

- अपराध दर में कमी आई है, परंतु सुरक्षा को लेकर बनी धारणा और राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ निवेशकों को हतोत्साहित करता है।
- उदाहरणः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ NCR जिलों को बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण प्राथमिकता देती हैं।

5. श्रम बाजार में कौशल की कमी

- बड़ी संख्या में श्रमिक अप्रशिक्षित या अर्ध-प्रशिक्षित हैं।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी औद्योगिक उत्पादकता को प्रभावित करती है।
- PLFS 2022-23 के अनुसार, केवल 6.4% यूपी के कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है।

6. लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय पहुंच की कठिनाई

- राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है।
- एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

7. पर्यावरणीय नियमों और अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ

- प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनुपालन की कमी के कारण उद्योगों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है।
- उदाहरणः कानपुर की चमड़ा इकाइयाँ गंगा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के चलते कई बार बंद की गई हैं।

8. निवेश इरादे का क्रियान्वयन में रूपांतरण कम

- हस्ताक्षरित MoUs के क्रियान्वयन में देरी से नीति-नियोजन की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
- उदाहरणः 2023 में 33.5 लाख करोड़ के MoUs पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन उनका केवल एक छोटा हिस्सा ही क्रियान्वयन की स्थिति में पहुँचा है।

अपनी आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश को निवेश के इरादे और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना होगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना, पिछड़े क्षेत्रों में कारोबारी माहौल में सुधार लाना और कौशल विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

एक संतुलित, समावेशी और कार्यान्वयन-केंद्रित दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को भारत के लिए एक प्रमुख विकास इंजन में बदल देगा।

Chronicle ias

प्रश्न.5 उत्तर प्रदेश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित कीजिए।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (यूपी), जो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्यों में से एक है, की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है।

राज्य की भौगोलिक स्थिति उत्तर और पूर्वी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में कार्य करती है।

"एक जिला एक उत्पाद (ODOP)" और औद्योगिक कॉरिडोर जैसी सरकारी पहलों के साथ, ये क्षेत्र राज्य की आर्थिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

1. औद्योगिक क्षेत्र: विविध लेकिन असंतुलित

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान:**
  द्वितीयक क्षेत्र (सेकेंडरी सेक्टर) यूपी की GSDP में लगभग 25% का योगदान करता है। (उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023)
- **प्रमुख उद्योग:**
  - वस्त्र और हस्तशिल्प (जैसे: वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ, लखनऊ की चिकनकारी)
  - चमड़ा उद्योग (मुख्यत: कानपुर और उन्नाव)
  - खाद्य प्रसंस्करण (कृषि प्रधान राज्य होने के कारण)
  - इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण (नोएडा और ग्रेटर नोएडा में)
- **औद्योगिक कॉरिडोर:**
  - यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो 6 जिलों में फैला है।
  - पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे (Dedicated Freight Corridors) - औद्योगिक टाउनशिप के विकास में सहायक
- **चुनौतियाँ:** आधारभूत ढांचे में कमी, नियामक बाधाएं और औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

2. व्यापार और वाणिज्य: औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़

- **घरेलू व्यापार:**
  यूपी एफएमसीजी, कृषि इनपुट और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार है।
- **प्रमुख व्यापारिक केंद्र:**
  लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि शहर व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हैं।
- **प्रमुख निर्यात वस्तुएँ:**
  हस्तशिल्प, कालीन, चमड़े के उत्पाद, वस्त्र आदि।
- **निर्यात आँकड़े:**
  2022-23 में यूपी ने लगभग ₹1.76 लाख करोड़ का निर्यात किया।
  - प्रमुख बाजार: अमेरिका, यूएई और यूरोप

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

❖ **ई-कॉमर्स का विस्तार:**

नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफार्मों के लिए लॉजिस्टिक्स केंद्र बन रहे हैं।

❖ **ODOP योजना:**

विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर व्यापार को प्रोत्साहित करती है।

❖ **यूपी निर्यात संवर्धन नीति 2020:**

लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम): व्यापार और उद्योग के प्रमुख प्रेरक

❖ उत्तर प्रदेश में 95 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ हैं – देश में सबसे अधिक।
❖ लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। (MSME मंत्रालय)
❖ ये इकाइयाँ घरेलू व्यापार और निर्यात दोनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
❖ इन्हें विभिन्न क्रेडिट योजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्कों द्वारा सहायता दी जा रही है।

4. आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक्स

❖ **एक्सप्रेसवे:**

पूर्वांचल, यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाओं ने व्यापार और उद्योग की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है।

❖ **अन्य विकास:**

- ड्राय पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क
- प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जैसे: जेवर)
- इनसे वाणिज्य को और अधिक बल मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहे हैं। इनका योगदान रोजगार सृजन, निर्यात और GSDP में लगातार बढ़ रहा है। सरकारी नीतियों और आधारभूत ढांचे के विकास से यह प्रक्रिया और तेज हुई है। हालांकि, क्षेत्रीय विषमता, कौशल की कमी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इनका समाधान कर उत्तर प्रदेश समावेशी और सतत आर्थिक विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा सकता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.6 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महाकुंभ 2025 के आर्थिक महत्व का परीक्षण करें।

उत्तर- प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने धार्मिक परंपरा और आर्थिक विकास के संगम का एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं को 45 दिनों में आकर्षित कर यह आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख प्रेरक बना। इस आयोजन के विशाल पैमाने, डिजिटल अधोसंरचना के समावेश, और रोजगार सृजन ने राज्य की पहचान एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में सुदृढ़ की।

1. पर्यटनः एक प्रमुख आर्थिक इंजन

- घरेलू और विदेशी पर्यटकों की भारी आमद से राज्य की अर्थव्यवस्था में ₹1.5 लाख करोड़ ($18 बिलियन) का योगदान हुआ।
- होटलों, गेस्ट हाउसों और अस्थायी आवासों में उच्चतम बुकिंग दरों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिला।
- परिवहन, भोजनालयों, टूर ऑपरेटरों और खुदरा व्यापार जैसे स्थानीय व्यवसायों में मांग बढ़ी, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बल मिला।

2. रोजगार सृजनः एक सामाजिक-आर्थिक प्रोत्साहक

- 6 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित हुई, जिनमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र शामिल थे।
- लॉजिस्टिक्स, स्वच्छता, सुरक्षा, और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कार्यबल की माँग में वृद्धि हुई।
- लगभग 45,000 परिवारों ने तंबू लगाने, सुविधाएँ संचालित करने और पारंपरिक सेवाएँ प्रदान कर आय अर्जित की।
- हस्तशिल्प उद्योग ने ₹35 करोड़ का कारोबार किया, जिससे स्थानीय कारीगरों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिला।

3. आधारभूत संरचना विकासः दीर्घकालिक निवेश

- राज्य सरकार ने ₹6,382 करोड़ से अधिक की राशि सड़कों, फ्लाईओवरों, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और रिवरफ्रंट विकास में निवेश की।
- **प्रमुख परियोजनाएँ:**
  - गंगा नदी पर छह लेन का पुल
  - 275 करोड़ की लागत से बना चार लेन रेलवे ओवरब्रिज
  - 1.5 लाख शौचालय, 3,000 रसोईघर, और 11 अस्थायी अस्पताल, जो भविष्य में उपयोग हेतु स्केलेबल हैं।
- ये संरचनाएँ प्रयागराज की शहरी प्रगति और संपर्क व्यवस्था में दीर्घकालिक लाभ देंगी।

4. राजस्व और व्यापक आर्थिक प्रभाव

- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व ₹25,000 करोड़ से अधिक रहा:
  - जीएसटी और पर्यटन कर
  - वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री
- कुंभ के दौरान आर्थिक लेन-देन का अनुमान ₹2-3 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो इसके वृहद आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
- प्रभाव परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, कृषि, रिटेल और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों तक फैला।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

5. **डिजिटल और तकनीकी नवाचार**
- "डिजिटल महाकुंभ" के रूप में ब्रांडिंग:
  - AI आधारित निगरानी, फेसियल रिकग्निशन, अंडरवॉटर ड्रोन, और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सुरक्षा, सफाई और रीयल-टाइम सहायता सुनिश्चित की गई।
  - 2,760 CCTV कैमरे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCCs), और बहुभाषीय चौटबॉट्स ने भीड़ और आयोजन प्रबंधन को आधुनिक रूप दिया।
- इन नवाचारों ने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश के प्रति विश्वास को बढ़ावा दिया।

6. **वैश्विक मान्यता और सांस्कृतिक कूटनीति**
- महाकुंभ पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी ने "ब्रांड उत्तर प्रदेश" को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई।
- इससे आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को बल मिला।

7. **पर्यावरणीय और व्यवस्थात्मक चुनौतियाँ**
- भीड़ नियंत्रण में खामी के कारण एक दुखद भगदड़ की घटना सामने आई।
- कचरा प्रबंधन और जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियाँ बनी रहीं।
- नव निर्मित संरचनाओं की दीर्घकालिक देखरेख और उपयोग हेतु बजटीय प्रावधान व प्रशासनिक निगरानी आवश्यक है।

महाकुंभ 2025 यह दर्शाता है कि किस प्रकार धार्मिक आयोजन को आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार सृजन, संरचना विकास, और तकनीकी नवाचार के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
यह आयोजन परंपरा और आधुनिकता का सफल संगम था, जिसने उत्तर प्रदेश के लिए एक स्थायी आर्थिक विरासत छोड़ी।
हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि:
- **सतत नीतियाँ** बनाई जाएँ,
- **स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी** को समावेशी रूप से मान्यता मिले,
- और **डिजिटल प्रशासन** व **शहरी नियोजन** में निरंतर निवेश किया जाए।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.7 उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 के प्रमुख उद्देश्यों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर- भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं, विशेष रूप से इसके मजबूत औद्योगिक आधार और कुशल मानव संसाधन के कारण।

इन संभावनाओं को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020-25 की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और राज्य को एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

नीति के मुख्य उद्देश्यः

1. निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
- पारंपरिक और उभरते उत्पादों में मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता मानकों और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन।
- तकनीकी उन्नयन और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने हेतु सहायता।

2. अवसंरचना विकास
- ड्राई पोर्ट्स, टेस्टिंग लैब्स, इनलैंड कंटेनर डिपो, और फ्रेट कॉरिडोर जैसी निर्यात-अनुकूल संरचनाओं का निर्माण।
- "एक जिला एक उत्पाद (ODOP)" योजना के तहत जिला स्तरीय निर्यात केंद्र का संचालन।

3. संस्थागत सहयोग
- राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना।
- पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी, और गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसे वित्तीय प्रोत्साहन।

4. बाजार विविधीकरण और प्रचार
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, B2B बैठकें, और खरीदार-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- नए और गैर-पारंपरिक बाजारों तक पहुँच का विस्तार।

5. कौशल विकास और रोजगार सृजन
- कारीगरों, MSMEs, और श्रमिकों को पैकेजिंग, लेबलिंग, और ई-कॉमर्स से जुड़े कौशल में प्रशिक्षित करना।
- निर्यात-आधारित आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना।

नीति का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभावः

1. निर्यात वृद्धि
- 2019-20 में ₹89,000 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹1.57 लाख करोड़ तक निर्यात में वृद्धि (DGFT डेटा)।
- हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि प्रसंस्करण, और चमड़ा उत्पाद जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

2. MSME और कारीगर सशक्तिकरण

- ODOP योजना ने पारंपरिक उद्योगों जैसे मुरादाबाद की पीतल कला, कन्नौज का इत्र, और भदोही की कालीनों को पुनर्जीवित किया।
- घरेलू उद्योगों का औपचारिकीकरण, बेहतर बाजार पहुँच और आय स्थिरता सुनिश्चित की।

3. रोजगार सृजन

- निर्यात-आधारित माँग से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि।
- विशेषकर वस्त्र, हस्तशिल्प, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि।

4. अवसंरचना को बढ़ावा

- डैडरी और मुरादाबाद में ड्राई पोर्ट्स, और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास हुआ।
- पूर्वी मालवहन गलियारे (Eastern Freight Corridor) में राज्य की भागीदारी से बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों से संपर्क बेहतर हुआ।

5. व्यापार करने की सुगमता में सुधार

- निर्यात प्रलेखन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया गया।
- "उद्यमी मित्र हेल्पलाइन" और डिजिटल पोर्टलों की स्थापना से निर्यातकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ।

6. राज्य की जीएसडीपी में योगदान

- निर्यात वृद्धि से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा, जिससे राज्य की आर्थिक विविधता में वृद्धि हुई।
- कृषि संकट की स्थिति में गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन मिला।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- कुछ क्षेत्रों में अब भी अवसंरचना और बिजली आपूर्ति की समस्याएँ बनी हुई हैं।
- नीति की सफलता सभी जनपदों में समान नहीं रही—कुछ ODOP उत्पाद बाजार से जुड़ाव या ब्रांडिंग में पीछे हैं।
- वैश्विक आर्थिक अस्थिरता (जैसे: कोविड-19 के बाद की रिकवरी, आपूर्ति शृंखला संकट) से निर्यात में निरंतर वृद्धि को चुनौती मिली।

उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020–25 ने राज्य की जनसांख्यिकी और औद्योगिक क्षमताओं का प्रभावी दोहन किया है।

अवसंरचना विकास, संस्थागत सहयोग, और ODOP के माध्यम से उत्पादों के प्रचार पर बल देकर इस नीति ने निर्यात में वृद्धि की, MSMEs को सशक्त किया, और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। हालाँकि, 2025 तक इस नीति की वास्तविक परिवर्तनकारी क्षमता को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि निरंतर निवेश, सख्त निगरानी, और नीतिगत सुधार किए जाते रहें।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.8 उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो और शहरी परिवहन परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर– तेजी से होते शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। यातायात भीड़, प्रदूषण और अपर्याप्त गतिशीलता की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ जैसे शहरों में मेट्रो रेल और शहरी परिवहन अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख मेट्रो और शहरी परिवहन परियोजनाएँ:

- लखनऊ मेट्रो (2017 से संचालन में)
- कानपुर मेट्रो (2021 से आंशिक रूप से संचालन में)
- आगरा मेट्रो (निर्माणाधीन; 2023 में ट्रायल रन प्रारंभ)
- वाराणसी मेट्रो / लाइट मेट्रो परियोजना (प्रस्तावित)
- मेरठ RRTS (तेज रफ्तार रेल पारगमन प्रणाली) – दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर (2025 तक पूर्ण)
- एकीकृत शहरी परिवहन परियोजनाएँ – स्मार्ट बसें, ई-रिक्शा, और बहु-माध्यमीय हब

सकारात्मक प्रभाव:

1. बेहतर शहरी गतिशीलता

- यात्रा समय में कमी और भीड़भाड़ वाले शहरों (जैसे लखनऊ, कानपुर) में सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय यात्रा की सुविधा।
- मेट्रो सेवाएँ यातायात अवरोधों से प्रभावित नहीं होतीं, जिससे नियमित समय पर यात्रा संभव होती है।

2. पर्यावरणीय लाभ

- निजी से सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव से कार्बन उत्सर्जन और ईंधन खपत में कमी।
- विद्युत आधारित मेट्रो परियोजनाएँ हरित गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं।

3. आर्थिक विकास और निवेश

- मेट्रो कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट – TOD)।
- अवसंरचना में निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन मिला।

4. रोजगार सृजन

- निर्माण, संचालन और रखरखाव में प्रत्यक्ष नौकरियाँ।
- सुरक्षा, आतिथ्य, खुदरा आदि जैसे सहायक क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर।

5. शहरी पुनर्निर्माण और अवसंरचना एकीकरण

- ई-रिक्शा, बसों और फुटपाथों जैसे फीडर सेवाओं से अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार।
- मेट्रो स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

1. उच्च पूंजीगत लागत

- मेट्रो परियोजनाएँ अत्यधिक पूंजी मांगती हैं और इनमें दीर्घ अवधि का निवेश आवश्यक होता है।
- प्रारंभिक चरण में कम यात्री संख्या के कारण राजस्व उत्पन्न करना एक चुनौती है।

2. अंतिम-मील कनेक्टिविटी की कमी

- फीडर सेवाएँ और पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढाँचे में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

3. सीमित नेटवर्क कवरेज

- वर्तमान मेट्रो नेटवर्क कुछ सीमित मार्गों तक सीमित है; यह संपूर्ण शहरी और अर्ध-शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

4. समन्वय और शासन संबंधी समस्याएँ

- शहरी परिवहन परियोजनाएँ अक्सर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से प्रभावित होती हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ एक-दूसरे से टकराती हैं।

उत्तर प्रदेश के मेट्रो और शहरी परिवहन परियोजनाओं ने राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात, पर्यावरण और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन शुरू कर दिए हैं।
हालांकि, इन परियोजनाओं का समग्र प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रयास आवश्यक हैं:

- मेट्रो नेटवर्क का विस्तार
- मल्टी-मोडल एकीकरण में सुधार
- वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना
- समावेशी और सुलभ परिवहन को प्राथमिकता देना

इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए शहरी नियोजन में सुधार, मजबूत शासन प्रणाली, और जनभागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे उत्तर प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन लोगों की पहली पसंद बन सके।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.9 उत्तर प्रदेश नई वन नीति के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 9% भौगोलिक क्षेत्र ही वनाच्छादित है, जिससे भूमि क्षरण, जैवविविधता की हानि, और जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता जैसी गंभीर पारिस्थितिकीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नवीन वन नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य वनों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

मुख्य उद्देश्यः

1. वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि

- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम-से-कम 15% हिस्से को वन अथवा वृक्षाच्छादित बनाना।
- यह लक्ष्य राष्ट्रीय मानकों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप है।

2. जैवविविधता संरक्षण

- दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक वन प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण।

3. आजीविका सृजन

- वनों पर आश्रित समुदायों के लिए ईको-टूरिज्म, गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) और सामुदायिक वानिकी के माध्यम से टिकाऊ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा।

4. जलवायु परिवर्तन शमन

- वनों को कार्बन सिंक के रूप में मान्यता देते हुए, पुनर्वनीकरण, जलग्रहण विकास और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र की बहाली को प्राथमिकता।

5. शहरी एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण

- लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में वायु प्रदूषण और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव से निपटने हेतु शहरी हरियाली और सड़क एवं नहर किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा।

प्रमुख विशेषताएँः

- **भागीदारी आधारित वन प्रबंधनः**
  - स्थानीय समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और इको-डेवलपमेंट समितियों के माध्यम से शामिल करना।
- **कृषि वानिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारीः**
  - किसानों को वृक्ष आधारित खेती के लिए प्रोत्साहन, और निजी निवेश को बंजर भूमि पर वृक्षारोपण हेतु बढ़ावा।
- **तकनीकी उपयोगः**
  - GIS, सैटेलाइट निगरानी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वन स्वास्थ्य की निगरानी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम।
- **संस्थागत सशक्तिकरणः**
  - वन विभाग का पुनर्गठन, क्षमतावर्धन, और विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

समालोचनात्मक विश्लेषण:

सकारात्मक पक्ष:

- नीति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जो पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाती है।
- विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता पर बल देने से जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की संभावना बढ़ती है।
- शहरी वानिकी से प्रमुख शहरों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने में मदद मिल सकती है।

सीमाएँ:

- वन क्षेत्र को 15% तक बढ़ाने में भूमि की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले जिलों में।
- सामुदायिक सशक्तिकरण केवल नीति वक्तव्यों तक सीमित रह सकता है यदि कानूनी और वित्तीय समर्थन नहीं मिला।
- निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता वनों के व्यावसायीकरण और जैवविविधता के ह्रास का कारण बन सकती है।

उत्तर प्रदेश की नवीन वन नीति एक दूरदर्शी पहल है जो पारिस्थितिक संतुलन की पुनःस्थापना और सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी प्रभावशीलता से लागू किया जाता है, विभागों के बीच समन्वय कितना मजबूत होता है, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी कितनी सक्रिय रहती है।

यदि संस्थागत सहयोग मजबूत किया जाए और लाभार्थियों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया जाए, तो यह नीति जनसंख्या और पारिस्थितिक दबाव से ग्रस्त राज्यों के लिए एक मॉडल नीति बन सकती है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.10 उत्तर प्रदेश में सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थिति और कृषि उत्पादकता पर इसके प्रभाव का परीक्षण करें।

उत्तर- भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषिप्रधान राज्य है, जहाँ कृषि राज्य की आर्थिक गतिविधियों और आजीविका का प्रमुख आधार है। राज्य में सिंचाई अवसंरचना कृषि उत्पादकता को स्थिर और बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। दशकों में यूपी ने नहरों, नलकूपों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की एक विस्तृत सिंचाई प्रणाली विकसित की है, परंतु इसकी प्रभावशीलता और स्थिरता मिश्रित रूप में देखी गई है।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई प्रणालियाँ

1. नहर सिंचाई

- सबसे पुरानी विधि, विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित।
- प्रमुख योजनाएँ: अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, सरयू नहर आदि।
- राज्य के लगभग 25% सिंचित क्षेत्र को कवर करती है।

2. नलकूप सिंचाई

- सिंचाई का प्रमुख साधन, विशेष रूप से जहाँ नहरों की पहुँच नहीं है।
- लगभग 70% सिंचित क्षेत्र नलकूपों पर निर्भर, जिससे भूजल पर अत्यधिक निर्भरता उत्पन्न हुई है।

3. लिफ्ट सिंचाई

- उन क्षेत्रों में प्रयुक्त जहाँ गुरुत्वाकर्षण आधारित नहरें संभव नहीं हैं।
- नदी क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में उपयोग, जिसके लिए पंपिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है।

4. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई

- सीमित लेकिन धीरे-धीरे बढ़ता उपयोग, विशेष रूप से सब्जियाँ और फल जैसी उच्च मूल्य की फसलों के लिए।
- वर्तमान में लगभग 5% क्षेत्र ही इस प्रणाली के अंतर्गत है; "हर बूंद अधिक फसल" (PMKSY) योजना इसे प्रोत्साहित कर रही है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ और उनके प्रभाव

1. अपर गंगा नहर परियोजना

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा।
- मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में रबी और खरीफ फसलों की उत्पादन स्थिरता में वृद्धि।

2. लोअर गंगा नहर परियोजना

- पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभावी; मुख्य फसलें: धान, गेहूँ, गन्ना।
- गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों में मानसून पर निर्भरता में कमी।

3. सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना (2021 में प्रारंभ)

- 9 पूर्वी जिलों में 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु।
- दशकों की देरी के बाद पुनः प्रारंभ होकर बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता में वृद्धि।

4. केन-बेतवा लिंक परियोजना (2021 में MoU पर हस्ताक्षर)

- भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में 2.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा और 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

5. **पूर्वी उत्तर प्रदेश सिंचाई विकास परियोजना**
- आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जैसे उपेक्षित क्षेत्रों को लक्षित।
- नहरों के पुनर्वास और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार का समन्वित प्रयास।

कृषि उत्पादकता पर प्रभाव

1. **फसल तीव्रता में वृद्धि**
- राज्य की फसल तीव्रता 160% से अधिक, जो बहु-फसली खेती और सिंचाई उपलब्धता को दर्शाती है।

2. **उपज की स्थिरता**
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुनिश्चित है, वहाँ गेहूँ और गन्ना की औसत उत्पादकता अधिक है।

3. **फसल विविधीकरण**
- सिंचाई से किसानों को केवल खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि सब्जियाँ, दालें और बागवानी फसलें उगाने की सुविधा।

4. **वर्षा पर निर्भरता में कमी**
- पूर्वी और मध्य यूपी में परियोजनाओं ने मानसून विफलताओं से होने वाले नुकसान को घटाया है।

सिंचाई अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियाँ

1. **भूजल का अत्यधिक दोहन**
- नलकूप आधारित सिंचाई ने गाजियाबाद, लखनऊ जैसे जिलों को "अत्यधिक दोहित" बना दिया है।

2. **नहर प्रबंधन में अक्षमता**
- खराब रखरखाव, गाद जमाव और रिसाव के कारण जल आपूर्ति की क्षमता में कमी।

3. **सूक्ष्म सिंचाई का सीमित प्रसार**
- सब्सिडी योजनाओं के बावजूद ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों का सीमित उपयोग।

4. **पर्यावरणीय और क्षेत्रीय असमानता**
- जलभराव, मृदा लवणता, और क्षेत्रों के बीच जल संसाधनों की असमान पहुँच जैसी समस्याएँ विद्यमान।

5. **वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी अड़चनें**
- कई परियोजनाएँ लागत बढ़ने, प्रशासनिक बाधाओं और समन्वय की कमी के कारण प्रभावित होती हैं।

आगे की राह

- **भूजल नियमन** हेतु पुनर्भरण और उपभोग की निगरानी।
- **नहर आधुनिकीकरण:** सीमेंट लाइनिंग, डिजिटल निगरानी और विकेन्द्रीकृत जल उपयोगकर्ता समितियों का गठन।
- **सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार:** लक्षित सब्सिडी और जागरूकता अभियान।
- **एकीकृत जल प्रबंधन:** सतही जल, भूजल और वर्षा जल संचयन का सम्मिलन।
- **सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP)** के माध्यम से सिंचाई ढांचे का बेहतर रखरखाव और संचालन।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई अवसंरचना राज्य की कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। विभिन्न बड़े परियोजनाओं ने कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, परंतु स्थिरता, न्यायसंगत पहुँच और दक्षता से संबंधित समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। एक एकीकृत, तकनीक आधारित, और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ सिंचाई प्रबंधन प्रणाली अपनाना आवश्यक है, जिससे राज्य की कृषि दीर्घकालिक रूप से सशक्त और जलवायु के प्रति लोचशील बन सके।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

खंड - ब

प्रश्न.11 उत्तर प्रदेश की उच्चावच और संरचना को आकार देने में गंगा के मैदान और विंध्य क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करें।

उत्तर- उत्तर भारत में स्थित उत्तर प्रदेश (U.P.) की स्थलाकृति दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित है – गंगा का मैदान और विंध्य क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों ने राज्य की प्राकृतिक संरचना, पारिस्थितिकी, आर्थिक गतिविधियों, और मानव बसावट के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है।

1. गंगा का मैदान: उपजाऊ समभूमि

a. प्रसार और निर्माण

- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भाग घेरता है।
- पश्चिम में यमुना से लेकर पूर्व में घाघरा नदी तक फैला है।
- यह मैदान गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक आदि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ (alluvial) अवसादों से बना है।
- तीन भागों में विभाजित:
  - **अपर गंगा मैदान** (पश्चिमी यूपी)
  - **मध्य गंगा मैदान** (मध्य यूपी)
  - **लोअर गंगा मैदान** (पूर्वी यूपी)

b. स्थलाकृति विशेषताएँ

- समतल और प्राय: सपाट भू-भाग, जिसमें नदियों की मोड़ और बाढ़ के मैदानों के कारण हल्के उतार-चढ़ाव पाए जाते हैं।
- दोआबों की उपस्थिति (जैसे: गंगा-यमुना दोआब)।
- आड़ी-तिरछी झीलें (oxbow lakes), दलदल (swamps) तथा तालों (tals) की भरमार।

c. महत्व

- कृषि केंद्र: उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण गेहूँ, धान, गन्ना जैसी फसलों की गहन खेती संभव।
- घनी आबादी: उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण अधिक जनसंख्या।
- परिवहन और नगरीकरण: समतल भू-भाग के कारण सड़क और रेल नेटवर्क का तीव्र विकास; लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों का विकास।

2. विंध्य क्षेत्र: दक्षिणी उच्चभूमि

a. प्रसार और भूगर्भिक संरचना

- दक्षिणी यूपी में स्थित, विशेष रूप से सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट जिलों में।
- यह क्षेत्र विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, जिसमें रेत पत्थर, चूना पत्थर, शेल जैसी प्राचीन तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं।

b. स्थलाकृति विशेषताएँ

- ऊँचा-नीचा (undulating) भू-भाग जिसमें पहाड़ियाँ, पठार और खड़ी ढालें (escarpments) शामिल हैं।
- ऊँचाई लगभग 300 से 600 मीटर; धीरे-धीरे गंगा मैदान की ओर ढलान।
- कटे-फटे पठार और बीहड़ क्षेत्र, विशेषकर केन और बेतवा नदियों के किनारे।

c. महत्व

- खनिज संसाधनों में समृद्ध: चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला – औद्योगिक उपयोग में सहायक।
- वन और जैव विविधता क्षेत्र: यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो वन्य जीवों के लिए उपयुक्त हैं।
- आदिवासी निवास एवं सांस्कृतिक स्थल: यहाँ आदिवासी समुदायों की बसावट और लखनिया दरी जैसी प्राचीन गुफा चित्रकला के स्थल स्थित हैं।
- जलविद्युत संभावनाएं: चट्टानी क्षेत्र में बहती नदियाँ जलप्रपात और बाँध निर्माण की संभावनाएँ (जैसे: रिहंद बाँध) उत्पन्न करती हैं।

3. दोनों क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया (Interplay)

- विंध्य उच्चभूमि, गंगा के मैदान के दक्षिणी किनारे का निर्माण करती है और प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है।
- विंध्य क्षेत्र की नदियाँ (जैसे: सोन, केन, बेतवा) मैदान की ओर प्रवाहित होती हैं और उर्वर मिट्टी और तलछट लेकर आती हैं।
- इन नदियों के निकासी तंत्र से गंगा मैदान की भूमि संरचना और नदी मार्ग प्रभावित होते हैं।

4. आर्थिक और पारिस्थितिकीय प्रभावः तुलनात्मक दृष्टिकोण

विशेषता	गंगा का मैदान	विंध्य क्षेत्र
मृदा प्रकार	जलोढ़, अत्यंत उपजाऊ	लाल, लेटराइटिक, कम उपजाऊ
कृषि	गहन कृषि (गेहूँ, धान, गन्ना)	सीमित कृषि (पठारी क्षेत्र के कारण)
उद्योग	कृषि आधारित, वस्त्र उद्योग	खनन, सीमेंट, ताप विद्युत उत्पादन
जल संसाधन	बहु जलप्रवाह, स्थायी नदियाँ	मौसमी नदियाँ और धाराएँ
जनसंख्या घनत्व	अत्यधिक सघन	विरल, कम जनसंख्या

गंगा का मैदान और विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और स्थलाकृति की पहचान को परिभाषित करते हैं। जहाँ गंगा मैदान ने राज्य को कृषि, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में सहारा दिया है, वहीं विंध्य क्षेत्र ने खनिज संपदा, पारिस्थितिक विविधता और जल संसाधनों में योगदान दिया है।

इन दोनों क्षेत्रों का आपसी संबंध न केवल प्रदेश की भौगोलिक बनावट को आकार देता है, बल्कि इसके आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परिदृश्य को भी दिशा प्रदान करता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.12 उत्तर प्रदेश में जल और पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण करें। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में उनके योगदान को अधिकतम करने के लिए कौन से नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (UP), जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और पर्यावरणीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज में सक्रिय है। जहाँ सौर ऊर्जा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, वहीं जलविद्युत और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी पर्याप्त अविकसित संभावनाएँ मौजूद हैं। उचित नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य के ऊर्जा मिश्रण को और अधिक संतुलित और स्वच्छ बना सकता है।

उत्तर प्रदेश में जलविद्युत (Hydro Energy) की संभावनाएँ

वर्तमान स्थिति:

- **स्थापित क्षमता (2024 तक):** लगभग 502 मेगावाट की बड़ी जलविद्युत क्षमता स्थापित है।
- **पंप स्टोरेज क्षमता:** लगभग 13,440 मेगावाट की पंप स्टोरेज संभावना है, जो पिक लोड प्रबंधन के लिए उपयोगी हो सकती है।
- लघु जलविद्युत परियोजनाएँ: राज्य के पहाड़ी और जल स्रोत युक्त क्षेत्रों में कई लघु परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **मौसमी निर्भरता:** जल प्रवाह में वर्ष भर समानता नहीं होने से विद्युत उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव:** बड़े बांधों से विस्थापन, वन कटाव, और पारिस्थितिक असंतुलन की आशंका रहती है।

नीति हस्तक्षेप (Policy Interventions):

1. **लघु जल परियोजनाओं को प्रोत्साहन:** दूर-दराज के क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग।
2. **अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण:** परियोजनाओं की तेजी से स्वीकृति के लिए एकल खिड़की प्रणाली, साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रावधान।
3. **पीपीपी मॉडल को बढ़ावा:** सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से निवेश और तकनीकी दक्षता को आकर्षित करना।

उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा (Wind Energy) की संभावनाएँ

वर्तमान स्थिति:

- **स्थापित क्षमता:** वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन नगण्य है; कुछ परियोजनाएँ केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में सीमित रूप से स्थापित हैं।
- **संभावित क्षमता (NIWE के अनुसार):**
  - **50 मीटर ऊँचाई पर:** ~138 मेगावाट
  - **80 मीटर ऊँचाई पर:** ~1,260 मेगावाट
- तकनीकी उन्नति के साथ राज्य में कम गति वाली हवा से भी विद्युत उत्पादन की संभावना बढ़ रही है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

मुख्य चुनौतियाँ:

- **कम हवा की गति:** राज्य के अधिकांश भागों में हवा की औसत गति कम है, जिससे पारंपरिक टर्बाइन कारगर नहीं हो पाते।
- **भूमि अधिग्रहण की समस्या:** भूमि स्वामित्व विवाद और वैकल्पिक उपयोग के कारण भूमि प्राप्ति में कठिनाई।

नीति हस्तक्षेप (Policy Interventions):

1. **पवन संसाधन मानचित्रण:** सम्पूर्ण राज्य में हवा की गति और दिशा का आकलन कर उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान।
2. **तकनीक का उन्नयन:** कम हवा की गति वाले क्षेत्रों के लिए विशेष टर्बाइनों को बढ़ावा देना।
3. **निवेश प्रोत्साहन:** सब्सिडी, टैक्स छूट एवं अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेश आकर्षित करना।
4. **स्थानीय भागीदारी:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित कर भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को कम करना और लाभ साझा करना।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश ने जहाँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है, वहीं जलविद्युत और पवन ऊर्जा अभी भी अल्प उपयोग में हैं। यदि निम्नलिखित नीति उपाय अपनाए जाएँ्र

- लघु जल परियोजनाओं का समर्थन
- पवन संसाधनों की वैज्ञानिक मैपिंग
- कम हवा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक
- स्थानीय सहभागिता और निवेश प्रोत्साहन

तो राज्य का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो अधिक विविध, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बन सकेगा। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक विकास को भी गति देगा।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.13 उत्तर प्रदेश के आर्थिक और रोजगार परिदृश्य पर औद्योगिक गलियारों के प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (UP), जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, ने हाल के वर्षों में औद्योगिक गलियारों के माध्यम से अपने औद्योगिक एवं अवसंरचना परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा (EDFC), और उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC) जैसे परियोजनाओं ने राज्य में औद्योगीकरण, आर्थिक विविधीकरण, और रोजगार सृजन को नया आयाम दिया है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक गलियारे:

1. दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC):

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद) से होकर गुजरता है।

2. अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC):

- पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वी राज्यों से जोड़ता है।

3. पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारा (EDFC):

- कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज आदि जिलों को पार करता हुआ एक प्रमुख लॉजिस्टिक धुरी है।

4. उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC):

- छह नोड्स को कवर करता है: अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ।

आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव:

1. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि:

- **क्लस्टर-आधारित विकास:**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स (नोएडा), टेक्सटाइल (कानपुर), और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग (अलीगढ़, झांसी) जैसे क्षेत्रों में तेजी।
- UPDIC में अब तक ₹24,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं।

2. अवसंरचना विकास:

- एक्सप्रेसवे (गंगा, पूर्वांचल), लॉजिस्टिक पार्क, और मल्टीमॉडल हब (दादरी, वाराणसी) का विकास।
- व्यापार, निवेश और आपूर्ति शृंखला की दक्षता में सुधार।

3. एफडीआई और घरेलू निवेश आकर्षण:

- प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से निवेशकों को भरोसा।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 1.9 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिनमें अधिकांश गलियारों से जुड़े।

4. नगरीकरण और रियल एस्टेट विकास:

- ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ में वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण रियल एस्टेट में तेजी।
- स्मार्ट टाउनशिप्स और सेवा क्षेत्र में बहुगुणित प्रभाव।

रोजगार परिदृश्य पर प्रभावः

1. रोजगार सृजनः

- निर्माण, लॉजिस्टिक्स, MSMEs, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार।
- केवल UPDIC से अगले दशक में 5 लाख से अधिक नौकरियों की संभावना।

2. MSME एकीकरणः

- बड़े उद्योगों और स्थानीय एमएसएमई के बीच सप्लाई चेन संबंध मजबूत।
- स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण हेतु स्किल डेवलपमेंट केंद्रों की स्थापना।

3. मानव पूंजी विकासः

- IIT कानपुर, AKTU, ITI आदि संस्थानों से साझेदारी कर मांग आधारित प्रशिक्षण।
- डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमेशन, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान।

चुनौतियाँ एवं समाधानः

मुख्य चुनौतियाँः

- भूमि अधिग्रहण में देरी, प्रशासनिक जटिलताएँ, और पर्यावरणीय बाधाएँ।

आवश्यक नीति उपायः

1. समावेशी विकास पर बलः

- बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी जैसे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।

2. अंतिम मील संपर्क (Last-Mile Connectivity):

- ग्रामीण उद्योगों को बाजार से जोड़ने हेतु मजबूत संपर्क।

3. तकनीकी शिक्षा का उन्नयनः

- नई तकनीकों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारे राज्य की संरचनात्मक आर्थिक रूपांतरण के इंजन बनकर उभरे हैं। ये गलियारे न केवल औद्योगीकरण और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि राज्य की भौगोलिक और आर्थिक संरचना को भी नया आकार दे रहे हैं।

परंतु, इस विकास को संतुलित और सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नीतिगत हस्तक्षेप समावेशी हों, व्यावसायिक अनुकूलन बढ़े, तथा कार्यबल कौशल उन्नयन को प्राथमिकता मिले।

यदि ऐसा किया गया, तो उत्तर प्रदेश एक श्रम-समृद्ध राज्य से एक औद्योगिक शक्ति केंद्र में परिवर्तित हो सकता है, जो भारत की GDP में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.14 उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों की भूमिका का परीक्षण करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (UP) में शहरीकरण पिछले दो दशकों में तीव्र गति से हुआ है, जिससे नगरपालिका ठोस कचरे की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। आज राज्य की 22% से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, ऐसे में कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सतत शहरी शासन का एक अत्यंत आवश्यक घटक बन गया है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीतियों के साथ समन्वय करते हुए कई योजनाएं और नीतिगत पहलें आरंभ की हैं ताकि शहरी कचरा संकट को नियंत्रित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट उत्पादन की वर्तमान स्थितिः

- राज्य के शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) प्रतिदिन लगभग 16,000–18,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
- कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी जैसे बड़े शहर इस कुल कचरे में बड़ा योगदान देते हैं।
- स्रोत पर कचरे का पृथक्करण (Segregation at Source) और उसका वैज्ञानिक निपटान अब भी अधिकांश द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सीमित है।

प्रमख अपशिष्ट प्रबंधन नीतियाँ एवं पहलें:

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

- **उद्देश्यः** 100% घर-घर संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, और वैज्ञानिक प्रक्रिया।
- 2024 तकः
  - 70% ULBs ने 100% संग्रहण लक्ष्य हासिल किया।
  - परंतु केवल 45% कचरे का ही वैज्ञानिक ढंग से निपटान हो रहा है।

2. राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (2022)

- विकेन्द्रित प्रबंधन, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज (MRFs), और वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों को बढ़ावा देती है।
- PPP मॉडल और जन-सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।

3. विरासत कचरा (Legacy Waste) का बायो–रिमेडिएशन

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश पर प्रयागराज और मेरठ जैसे शहरों में कार्य आरंभ।
- राज्य भर में 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक विरासत कचरे की पहचान कर उपचार प्रक्रिया चल रही है।

4. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन

- सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को बढ़ावा।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में।

5. अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण

- रैगपिकर्स (कचरा बीनने वाले) को पंजीकृत कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- 'सफाई मित्र सुरक्षा' योजना के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा रही है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

मुख्य चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** अधिकांश नगरपालिकाओं में उन्नत प्रसंस्करण इकाइयों (MRFs, कंपोस्टिंग, इन्सिनरेशन) की कमी।
- **कम नागरिक सहभागिता:** जन-जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की गति धीमी।
- **ULBs की क्षमता की कमी:** खासकर छोटे शहरों में प्रशिक्षित जनबल और वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव।
- **निगरानी और प्रवर्तन की कमजोरी:** नीतियों का एक समान क्रियान्वयन नहीं।
- **ई-वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट:** इनके निपटान हेतु समर्पित व्यवस्था की भारी कमी।

आगे की राह:

1. **विकेन्द्रित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ:**
   - वार्ड स्तर पर कंपोस्टिंग एवं बायोगैस संयंत्र से दक्षता बढ़ेगी और परिवहन लागत घटेगी।
2. **PPP मॉडल को मजबूती:**
   - निजी क्षेत्र को संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं ऊर्जा उत्पादन में निवेश हेतु प्रोत्साहन देना।
3. **डिजिटल निगरानी प्रणाली:**
   - गाड़ियों की ट्रैकिंग, कचरे की स्थिति, और रियल-टाइम डैशबोर्ड की शुरुआत से पारदर्शिता आएगी।
4. **संस्थागत क्षमता निर्माण:**
   - ULB कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण।
5. **नागरिक जागरूकता अभियान:**
   - स्कूलों, मीडिया, और RWA के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन और सहयोग को प्रोत्साहन।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के कारण विशेषकर बड़े शहरों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रौद्योगिकी और नीतिगत पहलों के माध्यम से सुधार दिखा है, परंतु छोटे नगरों तक इन उपलब्धियों को पहुँचाने में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। स्थायी, समावेशी और कुशल शहरी विकास हेतु आवश्यक है कि स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़े, जनभागीदारी सुनिश्चित हो, और कचरे को समस्या नहीं, संसाधन के रूप में देखा जाए ख्र जिससे आर्थिक, पर्यावरणीय, और रोजगार संबंधी लाभ प्राप्त हो सकें।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

Chronicle ias

प्रश्न.15 उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि के महत्व पर चर्चा करें। वे जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन में किस प्रकार योगदान करते हैं त्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि के महत्व पर चर्चा करें। वे जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन में किस प्रकार योगदान करते हैं

उत्तर- उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमियाँ न केवल पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं, बल्कि ये जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, और आजीविका के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों से परिपूर्ण यह राज्य 10 लाख हेक्टेयर से अधिक आर्द्रभूमियों से युक्त है, जो भारत की 13% अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ हैं।

I. जैव विविधता संरक्षण में भूमिका:

❖ **प्रमुख आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में:**

1. नवाबगंज पक्षी विहार (उन्नाव)

- रामसर साइट, 250+ पक्षी प्रजातियाँ
- प्रवासी पक्षी जैसे ग्रेलेग गूज और कॉमन टील देखे जाते हैं।

2. सरसई नावर झील (इटावा)

- सारस क्रेन (राजकीय पक्षी, संकटग्रस्त प्रजाति) का आवास।

3. हैद–रपुर वेटलैंड (मुजफ्फरनगर–बिजनौर)

- गंगा नदी की बाढ़ भूमि पर स्थित, मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद बना।
- गंगा डॉल्फिन, फिशिंग कैट और 300+ पक्षी प्रजातियां।

4. समसपुर (रायबरेली) और पार्वती अर्जा (गोंडा)

- देशी मछलियों और उभयचरों का आवास, ग्रामीण आहार व आजीविका हेतु आवश्यक।

II. जलवायु लचीलापन (Climate Resilience):

1. बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण

- बखिरा झील (संत कबीर नगर) जैसे वेटलैंड मानसून जल को समेटते हैं, जिससे पूर्वी यूपी की बस्तियों की रक्षा होती है।
- बखिरा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्रीय आर्द्रभूमि (28 किमी.), जो कृषि और जलस्तर बनाए रखती है।

2. कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration)

- सुर सरोवर (आगरा) और हैदरपुर जैसे वेटलैंड जैविक कार्बन को संग्रहित करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार।

3. गर्मी और सूखा से राहत

- बुंदेलखंड में छोटे तालाबों (जैसे बरुआसागर ताल, झांसी) के पुनरोद्धार से जल संकट में राहत मिली।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

III. सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्वः

1. मछली पालन और कमल की खेती से आजीविका

- बखिरा झील में 50,000+ मछुआरे निर्भर।
- पूर्वी यूपी में वेटलैंड में कमल की खेती से वैकल्पिक आय।

2. इको–पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व

- सुर सरोवर (कीठम झील) में पक्षी प्रेमी और पर्यटक आकर्षित होते हैं।
- प्रयागराज के संगम क्षेत्र के वेटलैंड धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े हैं।

IV. प्रमुख चुनौतियाँः

- अवैध अतिक्रमण – लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों में शहरी विस्तार से वेटलैंड समाप्त हो रहे हैं।
- प्रदूषण – हिंडन नदी के किनारे वेटलैंड में औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज।
- विखंडित शासन प्रणाली – वन, सिंचाई और शहरी निकायों में समन्वय की कमी।

V. नीति पहलें और आगे की राहः

a. नीतिगत एवं कानूनी उपायः

- आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का प्रभावी क्रियान्वयन।
- राज्य रिमोट सेंसिंग केंद्र (लखनऊ) द्वारा सैटेलाइट आधारित मानचित्रण।

b. समुदाय और पंचायत भागीदारीः

- जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) का निर्माण (गोरखपुर, गोंडा जिलों में)।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) की भागीदारी।

c. सरकारी योजनाएँः

- अमृत सरोवर मिशन (2022) – प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का विकास।
- मनरेगा और जल जीवन मिशन से वेटलैंड पुनरोद्धार में समन्वय।

d. पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र का संवर्धनः

- हैदरपुर और नवाबगंज जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रतिबंध और औद्योगिक अपशिष्ट पर रोक।

निष्कर्षः

उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के फेफड़े हैं – ये न केवल जैव विविधता की रक्षा करती हैं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, कार्बन संग्रहण, और स्थानीय आजीविका में भी सहायक हैं।

इनके संरक्षण हेतु आवश्यक है नीति कार्यान्वयन में पारदर्शिता, स्थानीय भागीदारी, और वैज्ञानिक पुनरोद्धार प्रयास। आर्द्रभूमियों को संपत्ति (asset) के रूप में देखना चाहिए, न कि बोझ के रूप में – जिससे एक संतुलित, टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.16 भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन करें।

उत्तर– भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अर्धचालक निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया और सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, राज्य ने दिल्ली–एनसीआर की भौगोलिक निकटता, नीतिगत प्रोत्साहन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बल पर यह स्थान अर्जित किया है।

I. उभरता हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रः

1. नोएडा–ग्रेटर नोएडा–यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र

- भारत का अग्रणी मोबाइल निर्माण क्लस्टर
- सैमसंग का नोएडा प्लांट दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माण संयंत्रों में शामिल।

2. प्रमुख कंपनियाँः

- Lava, Oppo, Vivo, और Dixon Technologies जैसी कंपनियों की उत्पादन इकाइयाँ।

3. उपलब्धियाँः

- भारत के 60% से अधिक मोबाइल उपकरण इस क्षेत्र में निर्मित।
- 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित।

II. सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगतिः

1. टाटा ग्रुप की पहल (2024)

- 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर ATMP (Assembly, Testing, Marking, Packaging) संयंत्र ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित।
- अनुमानित 30,000 रोजगार और भारत की पैकेजिंग क्षमताओं को बढ़ावा।

2. नीति समर्थनः

- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम व यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 के अंतर्गत सहायता।

III. उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील नीतियांः

1. यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानः

- पूंजी अनुदान – 25% तक।
- भूमि छूट और स्टांप शुल्क माफी।
- विद्युत दर और लॉजिस्टिक्स सहायता।

2. YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

- 300+ एकड़ भूमि अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए आवंटित।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

IV. चुनौतियाँ और संभावनाएँ:

प्रमुख चुनौतियाँ:

- वेफर फेब्रिकेशन जैसी उच्च तकनीक सुविधाओं की कमी।
- कुशल चिप डिजाइन इंजीनियरों की सीमित उपलब्धता।
- कच्चे माल और उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता।

प्रमुख अवसर:

- IIT कानपुर, IIIT लखनऊ जैसे संस्थानों से R&D और मानव संसाधन विकास।
- चिप डिजाइन स्टार्टअप और इनोवेशन क्लस्टर को बढ़ावा।
- ई-वेस्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकॉनमी मॉडल का विकास।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश, रणनीतिक निवेश और समर्थ नीतियों के बल पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। यह न केवल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति दे रहा है, बल्कि "मेक इन इंडिया" और डिजिटल संप्रभुता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

प्रश्न.17 उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर– उत्तर प्रदेश में कृषि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 24% हिस्सा प्रदान करती है और 60% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है।

इस परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल कृषि क्षेत्र में अवसंरचना, तकनीकी ज्ञान और बाजार से जुड़ाव की खाई को भरने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।

1. अवसंरचना विकास और कृषि–लॉजिस्टिक्स सुधार:

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज), गोदाम, और कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा मिला है।
- यह विकास राज्य कृषि उपज विपणन अधिनियम (APMC) सुधारों के अंतर्गत हुआ है, जिससे निजी निवेशकों को सुविधा मिली।

उदाहरण:

- मेगा फूड पार्क जैसी परियोजनाएँ – जैसे बाराबंकी और वाराणसी में – निजी कंपनियों की साझेदारी से विकसित की गईं, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई और मूल्य संवर्धन संभव हुआ।

2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कृषि विस्तार सेवाएँ:

- निजी एग्रीटेक कंपनियाँ जैसे एगनेक्स्ट (AgNext), देहात (DeHaat), एग्रीबाजार (AgriBazaar) राज्य के कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं।
- ये कंपनियाँ मृदा परीक्षण, फसल परामर्श, डिजिटल माध्यम से कृषि इनपुट की आपूर्ति जैसी सेवाएँ किसानों को दे रही हैं।

प्रभाव:

- इससे सटीक कृषि (प्रिसीजन फार्मिंग) को बढ़ावा मिला है, इनपुट का सही उपयोग हो रहा है और किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन आसान हुआ है।

3. बाजार से जुड़ाव और मूल्य श्रृंखला का एकीकरण:

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) तथा कांट्रैक्ट फार्मिंग जैसे प्रयास किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

उदाहरण:

- पेप्सिको (PepsiCo) और आईटीसी (ITC) जैसी कंपनियाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू और गेहूं की फसलों के लिए बीज आपूर्ति, प्रशिक्षण और निश्चित खरीद (Buyback Guarantee) प्रदान कर रही हैं।
- इससे किसानों को निश्चित आय और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त हो रहे हैं।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

4. क्षमता निर्माण और कौशल विकास:

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए सरकार किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को प्रशिक्षण, प्रबंधन क्षमता और बाजार से जुड़ने की क्षमता प्रदान कर रही है।

मुख्य चुनौतियाँ:

- भूमि समेकन की कठिनाई, नियामक अस्पष्टता, और छोटे किसानों में अविश्वास अभी भी इस मॉडल की सर्वव्यापकता में बाधा हैं।
- PPP परियोजनाओं की सफलता के लिए पारदर्शिता, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, और नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल ने अब तक अवसंरचना का विकास, तकनीकी नवाचार, बाजार से संपर्क, और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

फिर भी, इस मॉडल को और प्रभावशाली और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए, स्थानीय संस्थाओं (जैसे पंचायतों, सहकारी समितियों) को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए, और PPP परियोजनाओं के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी नीति लागू की जाए।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.18 उत्तर प्रदेश में जलीय कृषि, अंगूर कृषि, रेशम उत्पादन और पुष्प कृषि के विकास और क्षमता का विश्लेषण करें।

उत्तर– उत्तर प्रदेश (UP) में 9 कृषि-जलवायु क्षेत्रों, प्रचुर जल संसाधनों, और बड़ी कृषक आबादी की उपलब्धता ने राज्य को पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ाकर मूल्य संवर्धित सहायक कृषि क्षेत्रों की ओर उन्मुख किया है। मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन तथा पुष्प उत्पादन जैसे क्षेत्र राज्य में आय वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात आय के नए द्वार खोल रहे हैं।

1. मत्स्य पालन (Aquaculture):

विकास:

- उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पाँच अंतर्देशीय (inland) मछली उत्पादक राज्यों में शामिल है।
- वर्ष 2022-23 में मछली उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहा।

संभावनाएँ:

- राज्य के पास 28 लाख हेक्टेयर से अधिक मीठे पानी के स्रोत हैं, जिनके माध्यम से इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, केज कल्चर, और बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी सहायता:

- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
- राज्य मत्स्य नीति 2021 – मछली बीज उत्पादन, कोल्ड चेन विकास में सहायक।

2. अंगूर की खेती (Viticulture):

विकास:

- परंपरागत रूप से अंगूर उत्पादन में पिछड़े हुए, फिर भी बुंदेलखंड, मिर्जापुर और चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में ICAR और बागवानी मिशन योजनाओं के तहत अंगूर की खेती में प्रयोग हो रहे हैं।

संभावनाएँ:

- टेबल ग्रेप्स (खाने योग्य अंगूर), किशमिश उत्पादन, और यहां तक कि वाइन टूरिज्म की संभावना यदि तकनीकी मार्गदर्शन और सिंचाई सहायता मिलें तो साकार हो सकती है।

3. रेशम उत्पादन (Sericulture):

विकास:

- उत्तर प्रदेश भले ही पारंपरिक रेशम उत्पादक राज्य नहीं रहा, लेकिन अब सोनभद्र और चंदौली जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तसर और शहतूत रेशम (mulberry silk) का उत्पादन शुरू हो चुका है।

सरकारी पहल:

- सेंट्रल सिल्क बोर्ड और सिल्क समग्र योजना के तहत क्लस्टर विकास, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रशिक्षण व रोजगार मिल रहा है।

4. पुष्प उत्पादन (Floriculture):

विकास:

- पुष्प उत्पादन अब बाराबंकी, कन्नौज और गोरखपुर जैसे जिलों में तेजी से बढ़ रहा है, जहां से फूल शहरी बाजारों और धार्मिक स्थलों को आपूर्ति किए जाते हैं।

नीतिगत समर्थन:

- समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत फ्लोरीकल्चर क्लस्टर्स और निर्यात उन्मुख फ्लावर पार्क्स की स्थापना।

मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन और पुष्प कृषि जैसे उच्च मूल्य कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लिए कृषि विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के प्रमुख स्रोत बन सकते हैं।

यदि इन क्षेत्रों को तकनीकी सहायता, प्रभावी बाजार संपर्क (market linkages) और किसान जागरूकता, मिले तो यह राज्य के लघु और सीमांत किसानों को वैकल्पिक आजीविका का साधन देकर आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.19 उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के वितरण और आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। वे राज्य के औद्योगिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (UP) भले ही धात्विक खनिजों (metallic minerals) में अत्यंत समृद्ध न हो, लेकिन राज्य में गैर-धात्विक और औद्योगिक खनिजों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। ये खनिज निर्माण, सिरेमिक, कांच और सीमेंट उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका वितरण मुख्यत: विंध्यन भू-गठन और बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्रित है।

प्रमुख खनिजों का वितरण:

- **चूना पत्थर (Limestone):**
  - **जिले:** सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली
  - **उपयोग:** सीमेंट उद्योग के लिए अनिवार्य
- **डोलोमाइट (Dolomite):**
  - **जिला:** सोनभद्र
  - **उपयोग:** इस्पात (steel) और कांच निर्माण में
- **सिलिका बालू (Silica Sand):**
  - **जिले:** प्रयागराज (इलाहाबाद), मिर्जापुर, हमीरपुर
  - **उपयोग:** कांच और फाउंड्री उद्योगों में
- **जिप्सम (Gypsum):**
  - **जिले:** झांसी, ललितपुर
  - **उपयोग:** सीमेंट और उर्वरक उत्पादन में
- **बॉक्साइट (Bauxite):**
  - **जिला:** ललितपुर (छोटी मात्रा में)
  - **उपयोग:** एल्युमिनियम आधारित उद्योगों में
- **मैग्नेसाइट और पायरोफिलाइट:**
  - **जिले:** सोनभद्र, महोबा
  - **उपयोग:** अग्निरोधी सामग्री (refractory) और सिरेमिक उद्योग में
- **ग्रेनाइट और मार्बल (Granite & Marble):**
  - **क्षेत्र:** बुंदेलखंड
  - **उपयोग:** सजावटी पत्थर के रूप में खनन और निर्यात

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

आर्थिक महत्त्वः

- **राजस्व सृजनः**
  - खनन से राज्य को रॉयल्टी और पट्टा शुल्क के माध्यम से आय होती है।
  - वर्ष 2022–23 में उत्तर प्रदेश को खनन से ₹1,500 करोड़ से अधिक की आय हुई।
- **रोजगार सृजनः**
  - खनन क्षेत्र में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में।
- **ग्रामीण विकासः**
  - खनन क्लस्टर के आसपास परिवहन, औजार निर्माण और स्थानीय सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों का विकास होता है।

औद्योगिक विकास में योगदानः

- **सीमेंट क्लस्टरः**
  - सोनभद्र जिले में चूना पत्थर और जिप्सम की उपलब्धता के कारण यह सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है।
- **कांच और सिरेमिक उद्योगः**
  - फिरोजाबाद का कांच उद्योग स्थानीय सिलिका बालू पर निर्भर करता है।
- **पत्थर और मार्बल इकाइयाँः**
  - बुंदेलखंड में छोटे स्तर की कटिंग और पॉलिशिंग इकाइयाँ स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देती हैं।
- **बुनियादी ढांचे का विकासः**
  - ग्रेनाइट, बालू, और चूना पत्थर जैसे खनिजों की उपलब्धता निर्माण, सड़क, और रियल एस्टेट क्षेत्र में उपयोगी है।

निष्कर्षः

हालाँकि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की मात्रा सीमित है, फिर भी उनका उपयोग राज्य के औद्योगिक विविधीकरण, ग्रामीण रोजगार और क्षेत्रीय विकास को गति देता है। यदि इन खनिजों का सतत दोहन, आधुनिक तकनीक और पारदर्शी नियमन के साथ किया जाए, तो ये राज्य के आर्थिक विकास के स्तंभ बन सकते हैं।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.20 मानव संसाधन और कौशल विकास पर विशेष जोर देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं के लोगों के कल्याण पर प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर- भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश (UP) ने मानव विकास, रोजगार सृजन और कौशल विकास को केंद्र में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इन प्रयासों ने आजीविका सुरक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण, और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यानः

- **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनाः**
  - **उद्देश्यः** आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को UPSC, JEE, NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है।
  - **प्रभावः** ग्रामीण और वंचित तबकों को उच्च अवसरों तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **मिशन शक्तिः**
  - **उद्देश्यः** महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
  - **प्रभावः** महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि।
- **स्कूल आधारभूत संरचना सुधार (ऑपरेशन कायाकल्प):**
  - **कार्यः** 1.3 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में शौचालय, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी सुविधाएँ बढ़ाई गईं।
  - **प्रभावः** बुनियादी साक्षरता, छात्र प्रतिधारण, और शैक्षिक वातावरण में सुधार।

कौशल विकास और रोजगार सृजनः

- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM):**
  - **कार्यः** अब तक 15 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण; NSDC और निजी भागीदारों से साझेदारी।
  - **लक्ष्यः** उद्योग की माँग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना।
- **एक जनपद एक उत्पाद (ODOP):**
  - **कार्यः** पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार, कारीगरों को प्रशिक्षण, और निर्यात को प्रोत्साहन।
  - **प्रभावः** स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बल मिला।
- **स्टार्टअप नीति 2020:**
  - **सफलताः** 7,000 से अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, इन्क्यूबेशन और बीज पूंजी की सुविधा।
  - **प्रभावः** कुशल उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- **औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएंः**
  - **विवरणः** औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (जैसे- डिफेंस कॉरिडोर)।
  - **प्रभावः** उच्च-स्तरीय रोजगार क्षमता का सृजन।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

जनकल्याण और समावेशिता पर प्रभाव:

- **आजीविका में सुधार:**
  - कौशल विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन को कम किया, स्वरोजगार को बढ़ावा मिला।
- **समावेशी विकास:**
  - SC/ST, अल्पसंख्यकों, और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं ने राज्य में मानव पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन और सामाजिक उत्थान को प्रभावी रूप से प्रोत्साहित किया है। हालांकि, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल और निजी क्षेत्र के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता है, ताकि यह समावेशी विकास दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बन सके।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048